SHYAM LAL YADAV): (a) The production of foodgrains, State-wise, during the year 1987-88 is given in the enclosed statement. (*See* below).

(b) The National foodgrains production target for 1987-88 was fixed at 160 million tonnes. In order to achieve the same only working targets were indicated to the States.

(c) The Government took the following steps to help the States in raising the production level:—

(i) Maximisation of productivity in assured areas such as irrigaed areas and rainfed areas with high rainfall;

(ii) Timely, easy and adequate supply of agricultural inputs, inclusive of imparting improved technology;

(iii) Increasing the coverage of area under high yielding varieties with proper plans for production and distribution of sufficient seeds;

(iv) Implementation of the National Programme on crops like Special Ri Production Programme in the Eastermn States, National Pulses Development Projects and other programmes on resource management through Small and Marginal Farmers Programmes an National Watershed Development Programme;

(v) Adoption of integrated plant protection measures;

(vi) Increasing the intensity of cropping through double, multiple and intercropping; and

(vii) Assuring remunerative prices for various food crops to the farmers and organisational support for sale of commodities at these prices.

Statement

Production of Foodgrains during 1987-88 (*Provisional*)

	(Lakh tonnes)
Andhra Pradesh	96.9
Assam	29.3
Bihar	93.7
Gujarat	11.6
Haryana	62.9
Himachal Pradesh	9.3
Jammu & Kashmir	9.3
Karnataka	59.0
Kerala	10.8
Madhya Pradesh	141 4
Maharashtra	109.4
Orissa	51.6
Punjab	170 1
Rajasthan	43.3
Tmail Nadu	75.8
Uttar Pradesh	280 2
West Bengal	99 0
Others	16 6
ALL INDIA :	1370.2

गोदामों में क्षतिग्रस्त हुआ अनाज

1312. **श्री शरद यादव :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी गोदामों में रखा चावल और गेहूं क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1987-88 के दौरान कितनी मात्रा में अनाज क्षतिग्रस्त हुआ है ;

(ग) क्या भारतीय कृषकों और अर्थशास्त्रियों के आर्थिक दल ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं और इन सुझावों में से किन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्षा, बाढ़ों, तूफानों

आदि जैसे मानव नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से भण्डारण, परिवहन और बहु-हैंडलिंग के दौरान खाद्यान्नों का कुछ स्टाक क्षतिग्रस्त हो जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम, जोकि सरकारी स्टाक को हैंडल कर रही प्रमुख एजेंसी है, के पास पड़े हुए ऐसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का रखा गया औसत स्टाक (लाख मीटरी टन में)	ठोस से क्षतिग्रस्त अनाज में हस्तांतरित खाद्यान्नों की मात्रा (लाख मीटरी टन में)	औसत के प्रति क्षति की प्रतिशतता
1984–85 . . .	163.15	0.65	.49
1985–86 . . .	176.47	.87	0.49
1986–87 . . .	169.91	1.08	0.64
1987–88 . . .	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।		

(ग) और (घ) खाद्य विभाग को ऐसे किसी समाचार की जानकारी नहीं है।

जनसंख्या के अनुपात से खाद्यान्न का उत्पादन

1313. **श्री शरद यादव**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न का कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि 1990 तक भारत की जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के अखिल-भारत अनुमान इस प्रकार हैं :—

वर्ष	उत्पादन (दस लाख मीटरी टन में)
1985–86 . . .	150.4
1986–87 . . .	144.1
1987–88 . . . (अंतरिम)	137.0

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Applications pending for registration before CIB

1314. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of applications pending before the Registration Committee of CIB for grant of registration under section 9(3) and 9(3B) of the Insecticides Act and since when; and